लोकप्रिय लेकिन उद्देश्यपूर्ण बजट : अक्षत खेतान

मुंबई। आज प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार की सशक्त मंशा को दशार्ता है, जो निरंतर, अनुकूलनीय और दूरदर्शी संरचनात्मक सुधारों पर आधारित है। भारत की लगभग 7% की विकास दर, गरीबी में कमी और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता के साथ, यह बजट स्पष्ट रूप से आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और क्षमता को प्रदर्शन में बदलने का लक्ष्य रखता है। बजट की मूल भावना विकसित भारत संवाद और युवा-शक्ति प्रेरित दृष्टिकोण से जुड़ी है, जिसे तीन स्पष्ट कर्तव्यों द्वारा दिशा दी गई है—आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण करना तथा सबका साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप समावेशी प्रगति सुनिश्चित करना। अव कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज, संस्थापक-अक्षत खेतान ने कहा।

इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसका गतिशील संरचनात्मक सुधारों पर जोर है। विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अपनाने और केंद्र-राज्य स्तर पर चल रहे विनियमन-शिथिलीकरण प्रयास, सरकार के आधुनिक और व्यावहारिक नीति दृष्टिकोण को

दशार्ते हैं। विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्तावित रणनीतिक हस्तक्षेपों का उद्देश्य चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और भविष्य की वृद्धि के लिए शहरों के इकोसिस्टम को विकसित करना है।

यह बजट गहन क्षेत्रीय विश्लेषण और तकनीकी तैयारी को भी दशार्ता है। बायो-फार्मा शक्ति परियोजना, सेमीकंडक्टर मिशन और बुनियादी ढांचे के लिए लक्षित समर्थन, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के निर्माण के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक, कृषि से लेकर प्रौद्योगिकी तक, यह बजट लगभग हर वर्ग और क्षेत्र को संबोधित करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नीति निर्धारण से पहले विस्तृत होमवर्क किया गया है।

कपड़ा क्षेत्र को इस बजट में बड़ा प्रोत्साहन मिला है—नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल क्लस्टर विकास और मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत खादी पर नया जोर एक उल्लेखनीय कदम है, जो विरासत और आधुनिक आर्थिक प्रासंगिकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। साथ ही, 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार पारंपरिक औद्योगिक ताकत को आधुनिक वैल्यू चेन से जोड़ने में सहायक होगा।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। 10,000 करोड़ के एमएसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा एक बड़ा और स्वागतयोग्य कदम है। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत फंड, तरलता समर्थन, सीपीएसई के लिए टीआरईडीएस को अनिवार्य निपटान मंच बनाना और सीजीटीएमएसई के तहत इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसी पहलें एमएसएमई को मजबूती देंगी। आईसीएसआई, आईसीएआई और आईसीएमए के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र विकसित कर पेशेवर सहयोग उपलब्ध कराना, एमएसएमई की शासन क्षमता और विकास को नई दिशा देगा।